वर्ष 2 अंक 8 अगस्त 1980 50 पैसे

# सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

### प्रधानमंत्री की ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ वार्ता

# सरकार की नीतियों में मूल परिवर्तन के लिए सीटू का आह्वान

प्रधान मंत्री ने 'आर्थिक कार्यवाही' पर एक जुलाई को नई दिल्ली में ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ बातचीत की. विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों के 16 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया. सीटू की ओर से महासचिव पी. राममूर्ति ने इसमें भाग लिया.

बैठक के लक्ष्य को बताते हुए प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में आर्थिक हालात पर चिंता व्यक्त की और देश को 'कम उत्पादन-ऊंचे दामों' की पकड़ से बाहर निकालने की जरूरत पर जोर दिया. प्रधान मंत्री ने कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है, इसके लिये समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा एकजुट कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारतीय मजदूर अपने उत्तरदायित्व के प्रति आमतौर पर सजग हैं और उन्होंने कई कठिनाइयों जो उनके कारण नहीं हैं, के बावजूद अर्थ व्यवस्था को जारी रखा है.

बैठक को संबोधित करते हुए सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने कहा कि हम मजदूर वर्ग से संबंध रखने वाले ट्रेड यूनियन नेता मजदूर वर्ग की केवल आर्थिक समस्याओं में ही दिलचस्पी नहीं रखते हैं. कहां तक आप सोचते हैं कि हम बोनस, महंगाई भत्ता और केवल इस तरह की चीजों के लिए संघर्ष में समय बिताकर संतुष्ट होंगे. हम जानते हैं कि मजदूर वर्ग के हित समूचे देश के हितों के साथ जुड़े हैं. जब उन्होंने समूचे देश के बारे में कहा तो उनका मतलब आम जनता, मजदूरों, किसानों, व दलित वर्गों से था जिनसे देश बना है.

## क्रय शक्ति कम हो रही है

ग्रामीण मजदूरों जिसमें छोटे खेतहर मजदूर शामिल हैं की क्रय शक्ति दिन पर दिन घटती जा रही है. इसकी ओर इशारा करते हुए राममूर्ति ने कहा कि ये लोग देश में बनी आम जरूरियात की चीजों को भी नहीं खरीद पाते हैं. इसका असर मजदूर वर्ग पर पड़ता है. फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या हल होने की बजाए बढ़ जाती है. उन्होंने इस पर विश्वास जाहिर किया कि विभिन्न आदर्शों के बावजूद यदि ट्रेड यूनियन नेता एकजुट हो जाते हैं तो हम आर्थिक कार्यवाही के लिए एक आम कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं.

## अचूक दवा

लेकिन राममूर्ति ने कीमतों को नीचे लाने के लिए प्रधान मंत्री के रामबाण कि उत्पादन को बढ़ाया जाए पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि 15-20 सालों से यह अचूक दवा बतायी जा रही है. हर बार जनता को यह कहा गया कि उत्पादन बढ़ेगा दाम नीचे आ जाएंगे. उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ ? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी गहराई तक जाना जरूरी है.

## देश की अखंडता सबसे महत्वपूर्ण

सीटू के महासचिव ने कहा कि प्रधान मंत्री के भाषण में इस बात की ओर इशारा तक नहीं किया कि देश असम में समूचे उत्तरपूर्व में क्या हो रहा है जो देश की एकता और अखंडता पर ही असर नहीं डालता बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा असर डालता है. राममूर्ति ने कहा इससे मजदूर वर्ग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है. यहां उत्पादन बढ़ाने का नारा दिया जाता है लेकिन असम में नारा है 'धरती के लाल' और 'धरती के लालों को ही नौकरी और

[शेष पृष्ठ चार पर]

# त्रिपुरा फंड

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे के आह्वान पर सीटू यूनियन ने त्रिपुरा के उपद्रवों के शिकार लोगों सहायता के लिए विशेष अभियान चलाया. सीटू की पश्चिम बंगाल शाखा पहले ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के सहायता कोष में 10 हजार रुपये दे चुकी है. इसके अतिरिक्त वहां 30 हजार से भी ज्यादा रुपया जमा हो गया है तथा यूनियनें लगातार इस कोष के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं. बिहार राज्य कमेटी भी 500 रुपये भेज चुकी है. इस बीच त्रिपुरा सहायता कोष के लिए निम्नलिखित यूनियनों की ओर से चंदा मिला है.

## पश्चिम बंगाल

आनंद आफसेट व. एंड एंप. यू., 30 रु.; श्री अन्नापूर्णा काटन मि. यू., 300 रु.; बी. सी. एम. यू. गौरीपुर शाखा, 500, गौरीपुर कंटेनर एंड क्लो. ले. यू., 250, रबियालक व. एंड एंप. यू. 200, टैक्समैको व. यू., 1000, बी. सी. एम. यू. हुकमचंद, 100, बी. सी. एम. यू नैहती जूट, 100, जैसप म. यू., 1000, विमको म. यू., 101, इंडिया पेपर पल्प म. यू., 50, क्लोराइड एंड एक्साईड बैट्री व. यू., 101, मोहनी मि. (2) टैक्स. व. यू., 100, इंडिया टोबै. व. यू., 50, बरुईपुर पावरलूम व. यू., 25, प्रेसिजन इंड. वर्क. यू., 101, जैनसन एंड निकलसन स्टाफ एसो., 300 बी. सी. एम. यू. नाडिया ब्रांच, 250, बंगाल इनैमल श्रमिक कर्म. यू., 100, श्री लक्ष्मी काटन मि. व. यू., 100, दमदम एल. सी. नं. 5 टी. यू. संग. कमेटी, 1001, इंडिया आक्सी. व. यू., 500, मैटल एंड ओर्स व. यू, 100, सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. एंम. यू., 200 एम. सी. माउजी म. यू., 101, इजी. शिल्प श्र. यू., 101, फेवरेट स्माल इंवैस्ट. लि. एंम. यू., 501, ईस्ट. डायमड प्रो. एंड. यू., 25, पौलर्ज फैन व. यू., 101, पहारपुर व. एंम. यू., 1000, चैटर्जी पोर्क प्रा. लि. एंड सहयोगी उद्योग एंम. एंड व. यू., 25, कैरियर ट्रांस्पोर्ट एंम. यू., 500. ओबेरी ग्रैंड होटल कर्म. यू. 300, बस व. यू., 501, डिलक्स प्रा. लि. व. यू., 60, पिमरलैस संम. यू. 200, फर्मा के. एल. एम. कर्मचारी समिति, 101, नफारबाबू बा. एम. यू. 201, साविल्ज प्रा. लि. व. यू., 20, कलकत्ता पोर्ट एंड शोर म. यू., 1000, जे इंजी. व. यू., 200, इलैक्ट्रकल लैम्प व. यू., 2000, पार्क होटल एंम. यू, 150, कलकत्ता सिटी इटिंग एंड रिफ्रैश. एस्टै. व. यू., 250, सैं. कलकत्ता शाप्स एंम. एसो., 50, न्यू मार्किट शाप्स एंम. एसो., 20, बंगश्री आइस एंड कोल्ड एंम. यू., 20, वैस्ट बंगाल टेलर्ज यू., 100, डेज मेडिकल स्टोर्ज प्रा. लि. एंम. यू., 101, नार्थ ईस्ट कलकत्ता प्रेस व. एंम यू., 200, बेटवेट मजदूर कर्म. यू., 500, एलबर्ट डेविड एंम. यू., 100, कलकत्ता ट्रामवेज व. एंड एंम. यू., 500, नारायण चौधरी ब्र. व. यू., 50, हिमालय पेपर एंड बो. मि. म. यू., 100, ररौल बर्न लि. एम. यू. एंड आफि. एंड स्टाफ एसो., 420, हिंदुस्तान गैस एंड इंड म. यू, 501, कलकत्ता रबर व. एसो., 201, नेशनल रबर मैनु. म. यू., 101, स्टार टैक्श. एड एलाइड कसर्न व. यू., 100, सबर्बन इंजी. वर्क. यू., 200, कलकत्ता कार्पो. व. यू., 500, चिगवा एंड कं. व. यू., 50, डांक श्र. एसो., 500, गोल्डन स्टील कार्पो. एंम. यू., 101, बी. सी. एम. यू.(नस्करपुरा), 25, बी. सी. एम. यू. (हनुमान जूट), 25, एन. टी. सी. श्र. एंड एंम. यू. 100, बी. सी. एम. यू. सियालदाह, 100; बंगाल पोइरीज लि. म. यू. 101; हावड़ा मेटल एंड इंजी. व. यू हनु. इंड. ब्रांच, 100; अशोक ग्लास व. एम. यू., 50; बी. सी. एम. यू. नस्करपुर जूट मि. ब्रांच, 55; व. आफ फ्रैंड्स इलै. कं., 15; पीपल्ज इंजी. एंड मोटर वर्क्स व. यू., 50; बस व. यू. आर. टी. नं. 51, 54 व 56 यूनिट, 101; हावड़ा रबर व. यू. रूनी रबर इंड. यूनिट, 10; शंकर रबर प्रा. लि. यूनिट, 10; और विक्टोरिया रबर इंड. यूनिट, 10; इंडो स्टील फोर्ज प्रा. लि. वर्क. यू., 20; पिलानावाला प्लास्टिक कार्पो. व. यू., 10; वाटरप्रूफ इंड. व यू. 10; क्रोमि-लाइट इंडिया प्रा. लि. वर्क. यू., 25; हावड़ा मैटय एंड इंजी. व. यू. शं. सै. इंड. ब्रांच, 10; बोनस इंटर. ब्रांच, 10; हावड़ा मैटल एंड इंजी. व. यू. ब्राइट इड. ब्रांच, 10; और काली इंजी. ब्रांच, 10; डनलप व. यू., 1000; कल्याणी स्पि. मि. एभ. यू., 501; चा बागान म. यू., 1000; हैवी इंजी. कार्पो. एम. यू., 500; दुर्गापुर शाप्स एम. एसो., 50; डी. एस. पी एम. कार्पो. एम. यू., 50; ग्रेफाइट इंडिया लि. म. यू., 300; ए. बी. के. मेटल एंड इंजी. व. यू., 300; यूनाइटेड कंट्रैक्टर व. यू., 200; सेन रैले एंम. यू., 501; सैंट्रल काटन मि. एम. यू.. 50; बैलमेन इंकैडिसैंट एम. यू., 151; बी. सी. एम. यू. बेलुर, 100; बी. सी. एम. यू. बेली, 300; नल्ली मि. कर्म. सं., 101; ब्रिज एंड रूफ एम. यू., 151; ब्रिज एंड रूफ व. यू., 201; जी. के. डब्ल्यू. एच. ओ. वर्क्स एम. यू. 100; बै. बंगा. स्टेट से. रिप्रे. यू., 119; कलकता हौकर यू., 25; हौजरी श्र. यू., 100; के. आर. स्टील श्र. यू., 50; अरुण स्टील श्र. यू., 100; कलकता स्टेट ट्रां. एम. यू., 3000; कठगोला श्र. कर्म. यू., 50; पायोनियर निटिंग मि. एम. यू., 65; नार्थ कलकता इंजी. व. यू., 101; इंडियन स्टील कार्पो. कंसर्न एंम. यू., 51; पोर्ट इंजी. व. एंम. यू., 101; कलकता लोअर ग्रे. एंम. यू., 100; रसा डिस्टि. व. यू., 100; टेलीरामा व. यू., 50; ई. एम. सी. स्टील वर्क. यू., 1001; जी. आई. एस. आई. कर्म. सं., 101; पोस्टा श्र. सं., 501; बड़ा बा. म. यू., 250; नार्थ वैस्ट कलकता शाप्स एंड एस्टै. एंम. यू., 50; रंकल म. यू., 25; वैजमेन व. एंड एम. यू., 154; सिटी ड्रग यू., 20; आर. आई. सी. व. एंड एंम. यू., 200; डनबर काटन मि. व. यू., 100; एसो. आफ. 'सेल' एंप, कलकता, 4,501.

## महाराष्ट्र

भांडुप सीटू सेंटर, 2500; जनरल ले. यू. (ला. झंडा), 2000; अंधेरी

[शेष पृष्ठ सात पर]

# सीटू सैक्रेटेरियट की बैठक

सीटू सैक्रेटेरियट की बैठक सीटू के नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में एक जुलाई को हुई. बैठक के आरंभ में ही पी राममूर्ति ने 30 जून को केंद्रीय श्रम मंत्री टी अंजैया द्वारा बुलाई सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनो की मीटिंग का ब्यौरा दिया. इसके बाद बैठक में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जा रही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मीटिंग में सीटू द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दृष्टिकोण पर विचार किया गया.

बैठक में सीटू की जनरल काउंसिल की अगली बैठक को केरल में किए जाने के केरल सीटू के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया. यह बैठक 11 से 14 सितंबर के बीच होगी. सीटू की कार्य-समिति की बैठक 11 सितंबर को होगी तथा 14 सितंबर को एक रैली का आयोजन किया जाएगा.

अलग-अलग उद्योगों के स्तर पर बैठक काउंसिल की बैठक के एक दिन पहले होगी.

सीटू की केरल राज्य कमेटी भोजन को बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएगी किंतु साथियों को भी इस व्यवस्था के लिए कुछ धन देना पड़ेगा जो सदस्य उद्योग-स्तर की बैठकों में हिस्सा लेंगे उन्हें अपने भोजन का प्रबंध स्वयं ही करना पड़ेगा

बैठक में निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण उद्योग में काम कर रही यूनियनों के प्रनिनिधियों की एक बैठक जनरल काउंसिल की बैठक से एक दिन पहले की जाए. इस बैठक में भवन निर्माण उद्योग के मजदूरों की समस्याओं तथा उनकी मांगों को मनवाने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जाएगा.

बैठक में 1977 के लिए ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति की त्रुटियों पर बात चीत हुई. हमारी कई यूनियनों ने अपना वार्षिक लेखा समय पर नहीं भरा व कई अन्य यूनियनें सीटू से संबद्धता न दिखा पाई. इन कारणों से सीटू की सदस्य संख्या का निर्धारण वास्तविकता से बहुत कम हुआ.इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार ने हमारे खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया इस बारे में सीटू केंद्र ने सभी यूनियनों को एक पत्र भेजा है. बैठक में खेतिहर मजदूरों की यूनियनों को सीटू से संबद्ध करने का निर्णय भी लिया गया.

बैठक में निर्णय लिया गया कि ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के सवाल पर सीटू गुप्त मतदान के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करती रहेगी.

बैठक में आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन्न के इस सुझाव को मान लिया गया कि दो महीने में एक बार अंग्रेजी में एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाए. सैक्रेटेरियट ने अगस्त माह से यह बुलेटिन प्रकाशित करने का निर्णय लिया.

अक्तूबर माह में संसद के सामने कामगार महिलाओं के प्रदर्शन के सुझाव से यह तथ्य सामने आया कि संसद का अगला सत्र नवंबर के मध्य में होने की संभावना है जब कि दिल्ली का मौसम बहुत ठंडा होता है. सर्दी के मौसम में इस प्रकार के आम प्रदर्शन की कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि अक्तूबर में दिल्ली में प्रदर्शन के बजाय एक सम्मेलन आयोजित किया जाए. सम्मेलन को संयुक्त रुप से आयोजित किए जाने के लिए अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संपर्क स्थापित किया जाएगा.

कुछ नगरों में महिलाओं को रात्रि-पाली में काम करने देने के लिए नियमों को आसान बना दिए जान के कुछ सुझाव सामने आ रहे हैं.

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के विषय जनरल काउंसिल की अगली बैठक की कार्यसूची में रखे जाएं जिससे कि इन पर कोई निर्णय लेने से पहले खुली बहस की जा सके.

एस. एस. बोस, जिन्हें कि सीटू ने नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की महासभा का सदस्य नामजद किया था, ने इस महासभा के कामों में भाग लेने में अपनी असमर्थता जाहिर की हैं. सेक्रेटेरियट ने ने उनके स्थान पर बीरेन राय को इस काम के गिए मनोनीत किया है

बैठक ने ट्रेड यूनियन कक्षाओं के कार्यक्रम का जायजा लिया और निर्णय किया कि जहां कहीं भी राज्य कमेटियां इस प्रकार की कक्षाओं की मांग करें, वहां इनका आयोजन किया जाए.

बैठक में मजदूर वर्ग की आम समस्याओं पर एकजुट आंदोलन करने के प्रयत्नों पर विचार किया गया इस बारे में यह निर्णय किया गया कि कुछ तात्कालिक मुद्दों पर अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संपर्क स्थापित किया जाए जिससे कि इस दिशा में कुछ कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं. यह भी निर्णय किया गया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का कनफेडरेशन बनाने के प्रस्ताव जो अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के सामने रखा गया था, को आगे बढ़ाया जाए.

नृसिंह चक्रवर्ती ने यूगोस्लाविया में हुए 'विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

एम. के. पंधे ने इस वर्ष मास्को में आयोजित मई दिवस समारोह में सीटू के प्रतिनिधि के रुप में भाग लेने के लिए गए कमल सरकार की यात्रा का ब्यौरा दिया.


**सीटू का**
**नवीनतम प्रकाशन**
**खदानों में**
**कामगार महिलाओं की**
**दशा**
*(हिंदी)*
**कीमत 75 पैसे**
लिखें :
सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

## सीटू का आह्वान

[मुखपृष्ठ से आगे]

किसी को नहीं.' और यदि यह बात बढ़ती है तथा समूचे देश में फैलती है, जैसा कि अगर यह आंदोलन बल पकड़ता है तो होना अवश्यंभावी है, तो एक राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों के मजदूरों का गला पकड़ेंगे. यदि इस देश में ऐसा होता तो, और जब मजदूर वर्ग में इस आधार पर झगड़े होते हैं कि कौन किस राज्य से आया है तथा कौन कौन सी भाषा बोलता हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तब मजदूर वर्ग की क्या भूमिका होगी? बैठक में सीटू के महासचिव राममूर्ति ने बताया कि ऐसे हालात में मजदूर वर्ग कुछ नहीं कर सकता और किसी भी तरह का उत्पादन नहीं हो सकता. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में मजदूर वर्ग की एकता के इस नजरिये से हमारे लिए यह समस्या देश की एकता और अखंडता के आधार पर जनता के लिए इसकी महत्ता के साथ-साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है.

## प्रबंधन में भागीदारी

उत्पादन में मजदूर वर्ग को भूमिका और भागीदारी के संदर्भ में राममूर्ति ने कहा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित हमलोग अपने पहले वायदे पर कायम हैं कि हम समानता के आधार पर प्रबंधन के हर स्तर पर भाग लेने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यदि हमें प्रबंधन में केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए भाग लेना है तो हमे ऐसी भागीदारी स्वीकार्य नहीं है. यह भागीदारी प्रबंधन नहीं है. भागीदारी प्रबंधन का मतलब है समूची फैक्ट्री का प्रबंधन जिसमें उत्पादन, वितरण, खरीद, तकनीकी चुनना आदि शामिल है. यदि हमें इस तरह से भाग लेने दिया जाता है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, नही तो, उन्होंने कहा, भागीदारी प्रबंधन उत्पादन बढ़ाने के लिए एक साइन बोर्ड मात्र है जिसके तहत मजदूरों पर और ज्यादा कार्यभार यह कहकर लाद दिया जाएगा कि मजदूरों ने इसे स्वीकारा है.

## सरमायदारों का बचाव

सीटू के महासचिब ने कंपनी अफेयर्स मंत्रालय द्वारा गठित एक कमेटी को उस रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया जिसमें यह कहा गया है कि हाल ही के समय में कुछ बड़े व्यापारी घरानों ने जानबूझकर उत्पादन क्षमता को कम इस्तेमाल इस नजरिये से किया है ताकि उत्पादन घटाकर कीमतों में भारी वृद्धि की जा सके तथा जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सके. परंतु पार्लियामैंट में हमारे कहने के बाबजूद भी इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया. यह कह कर मना कर दिया गया कि इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा. लेकिन कैसे? यदि ऐसे आदमियों को जनता के सामने बेनकाब कर दिया जाता है तो उन पर दबाब डाला जा सकता है कि वे इस तरह की नीतियां जो समूचे देश पर असर डालती हैं तथा अर्थव्यवस्था को बिगाड़ती हैं, इस्तेमाल न करें. पी. राममूर्ति ने आगे कहा कि यदि सरकार इसी तरह से काम करती रही जबकि रिपोर्ट के मुताबिक एकाधिकारी व्यापारी सामान्य उत्पादन को जानबूझकर कम कर रहे हैं, तो उत्पादन के बारे में बातचीत करने से क्या फायदा.

## निजी क्षेत्र की चिल्लाहट

निजी क्षेत्र बहुत शोर मचा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नाकामयाब हो रहे हैं. इस ओर इशारा करते हुए सीटू के महासचिव ने याद दिलाया कि ये लोग यह भूल जाते हैं कि पिछले कई सालों में सैंकड़ों फैक्ट्रियां जिनका प्रबंधन निजी क्षेत्र ने किया था रुग्ण या बेकार हो गई हैं तथा सरकार को सैंकड़ों करोड़ों रुपये खर्च करके उनका अधिग्रहण करना पड़ा. वे पूरे धन को खा गए हैं.

यह चिल्लाहट इसलिए है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए और इसके शिकार मंत्री भी हो रहे हैं. हाल ही में ऊर्जा मंत्री गनी खां चौधुरी ने विद्युत केंद्रों को निजी क्षेत्र को सौंपने की बात यह कहते हुए कही कि यह इनका प्रबंधन राज्य विद्युत बोर्डों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है. प्रबंधन की खामियों का पता लगाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस बारे में राममूर्ति ने कई उदाहरण दिए कि जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र में जारी भ्रष्टता व खामियों को प्रबंधकों के ध्यान में लाया गया तो ट्रेड यूनियन आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया. कोई उचित छानबीन नहीं की जाती है या फिर यदि की भी जाती है तो केवल दिखाने के लिए. इसके बजाए ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं व यूनियन के पदाधिकारियों को उत्पीड़ित (विकिटमाइज) किया जाता है.

## स्वदेशी तकनीकी

तकनीकी-शास्त्रियों की ओर संकेत करते हुए सीटू के महासचिव ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक, तकनीकी-शास्त्री, और इंजीनियर किसी से भी कम नहीं हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें चुन-चुन कर भर्ती करती हैं तथा वे विदेशों में काम करने लगते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में फैसले उच्च स्तर पर लिए जाते हैं तथा इंजीनियरों को विश्वास में नहीं लिया जाता और उनके साथ सलाह-मशविरा नहीं किया जाता. दूसरी ओर यदि वे अपनी एसोसिएशन बनाते हैं तो उन्हें विकिटमाइज किया जाता है. इसके नतीजतन तकनीकी में कोई विकास नहीं होता है. राममूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी तकनीकी के विकास के लिए मजदूर वर्ग को विश्वास में लेना होगा.

## खास नजरिया

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने स्वदेशी तफनीकी को इस्तेमाल करके और इस बारे में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देकर मजदूर वर्ग में देशभक्ति की भावना जागृत करने पर जोर दिया. लेकिन जब हम एकाधिकारी घरानों को जबरदस्त मुनाफा कमाते और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मौजूद हर तरफ घांधली तथा स्वदेशी तकनीकी में कोई विकास नहीं देखते हैं तब मजदूर वर्ग में आप देशभक्ति की

[शेष पृष्ठ सौलह पर]

# स्वीडन में 1909 के बाद सबसे बड़ी हड़ताल

**अंतर्राष्ट्रीय समाचार**

2 मई को स्वीडन के 10 लाख से भी अधिक मजदूर एक विशाल हड़ताल पर गए. हड़ताल के कारण एक सप्ताह तक सभी उत्पादन केंद्र, यातायात, आम सुविधाएं व शिक्षा-संस्थान बंद रहे. 1909 की आम हड़ताल के बाद, जो कि स्वीडन के मजदूर वर्ग के इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती रही है, अब तक इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं आई.

2 मई को 10 लाख हड़ताली मजदूरों में से 1 लाख मजदूर एल. ओ. ट्रेड यूनियन केंद्र के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए. यह हड़ताल सरकार की आर्थिक व सामाजिक नीतियों के खिलाफ व वेतनवृद्धि के समर्थन में थी. मजदूरों की मांग 11% वेतनवृद्धि की थी जबकि मालिकों को केवल 3 प्रतिशत वृद्धि मंजूर थी तथा वह भी कई शर्तों के साथ. हड़ताल को तोड़ने के लिए मालिकों ने निजी क्षेत्र से 9 लाख मजदूरों को काम पर लगाने का फैसला किया. किंतु इससे भी हड़ताल को न तोड़ा जा सका. मालिकों ने मजदूरों को दंडित करने के उद्देश्य से 8 लाख मजदूरों को निलंबित कर दिया.

मजदूरों की मांगे इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि पिछले 4 वर्षों से सरकार की कर नीति से प्रति मजदूर की वार्षिक आय में 6 हजार स्वीडिश क्राउन की कमी हुई है. राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा है. पूंजी देश से बाहर निकल रही है व थाइलैंड, मलाया, दक्षिण कोरिया आदि ऐसे देशों में लगाई जा रही है जहां अमरीका का शिकंजा मजबूत है. इस कारण देश के भीतर नौकरियों की संभावनाएं खत्म हो रही हैं. इन हालात से स्वीडन का निर्यात कम हो गया है. उत्पादित माल बड़ी संख्या में भंडारों में पड़ा हुआ है तथा इसके बिकने की संभावनाएं कम हैं.

स्वीडिश एंप्लायर्ज फेडरेशन (एस. पी. एफ.) के इस निर्णय कि निजी क्षेत्र के मजदूरों के वेतन में 6.8% वृद्धि होगी, मजदूर काम पर लौट आए.

सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूर जो 25 अप्रैल से हड़ताल पर थे, 7.3% वृद्धि मिलने के बाद काम पर लौट आए.

मालिकान को वेतनवृद्धि इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हड़ताल के कारण स्वीडन को प्रतिदिन 40 से 60 करोड़ स्वीडिश क्राउन की हानि हो रही थी. इस राशि में अधिकतर मालिकों का मुनाफा ही था.

# श्रीलंका के मजदूरों पर दमन की सीटू द्वारा निंदा

**सी.** आई. टी. यू. के जनरल सेक्रेट्री संसद सदस्य पी. राममूर्ति ने 25 जुलाई को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू श्रीलंका की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति द्वारा घोषित आम हड़ताल के बर्बर दमन के लिए श्रीलंका सरकार की निंदा करती है. विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेशों पर चलते हुए श्रीलंका सरकार ने जो नीतियां अपनाई उनके कारण मुद्रास्फीति अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची. ऐसी हालत में मजदूरों के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं रह गया था कि वे न केवल अपने वास्तविक वेतन की रक्षा के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के हितों के लिए आम हड़ताल के माध्यम से अपने विरोध का इजहार करें. जुझारू मजदूर वर्ग की इस कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बतलाना सचाई पर पर्दा डालने के अलावा कुल नहीं है, अतः इमर्जेंसी लागू करना, बड़े पैमाने पर विक्टिमाइजेशन करना, रैलियों पर प्रतिबंध लगाना, प्रैस पर सेंसरशिप लगाना, यूनियनों का पैसा जब्त कर लेना और उनके दफ्तर बंद कर देना न केवल तानाशाहीपूर्ण कदम हैं बल्कि ऐसा करके संगठित होने के अधिकार और एसोसिएशन बनाने की आजादी जैसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परंपराओं पर भी आघात किया गया है.

सीटू श्रीलंका सरकार से इन दमनकारी आदेशों को वापस लेने तथा हड़ताली मजदूरों के साथ बातचीत के जरिये मामला तय करने की अपील करती है.

सीटू श्रीलंका के हड़ताली मजदूरों के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है तथा भारत के समूचे मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह श्रीलंका सरकार की दमनपूर्ण हरकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करे.

**जापान**

# महिला कामगारों के प्रति भेदभाव

**टो**क्यो में स्थानीय सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 75 प्रति शत कामगार महिलाओं ने बताया कि उनके प्रति भेदभाव किया जाता है. उन्होंने अपनी शिकायतें इस क्रम में रखीं—मजदूरी (70.5 प्रतिशत), ग्रेडिंग (31.5 प्रति शत), काम का बंटवारा (22.1 प्रति शत) व प्रशिक्षण (19.4 प्रति शत).

भेदभाव की शिकार महिलाओं में से केवल 19.7 प्रति शत महिलाओं ने ही हालात को ठीक करने की दिशा में कुछ कदम उठाए थे. इनमें से 59.1 प्रति शत अपनी ट्रेड यूनियनों को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, 48.7 प्रति शत ने इन्हें दूर करने के लिए मालिकों से सम्पर्क किया तथा 24 प्रति शत ने श्रम अधिकारियों से परामर्श लिया.

# संसार में अभी कितना तेल व कोयला संचित है

संचय शब्द का मतलब कच्चे माल की उस मात्रा से है जो मौजूदा आर्थिक व तकनीकी स्थितियों में भविष्य में प्रयोग के लिए भूमि से उसके ज्ञात संचय स्थानों से निकाला जा सकता है.

इससे यह जानकारी मिलती है कि विश्व संचय हर साल इसलिए बढ़ता है क्योंकि उन नये संचय स्थलों की खोज होती है जिनसे पहले कच्चा माल निकालना लाभकारी नहीं समझा जाता था और अब वे वैज्ञानिक व तकनीकी सुधारों के कारण आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बन गये हैं. आयात किये गये कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण अलाभकारी समझे जाने वाले संचय-स्थल, लाभकारी बन सकते हैं.

## विश्व तेल संचय

*(लाख टन में)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सउदी अरबिया | 2,24,800 |
| 2. | सोवियत यूनियन | 96,600 |
| 3. | कुवैत | 91,100 |
| 4. | ईरान | 80,000 |
| 5. | ईराक | 43,000 |
| 6. | आबू ढाबी | 40,000 |
| 7. | अमेरिका | 38,400 |
| 8. | लिबिया | 31,900 |
| 9. | चीन | 27,000 |
| 10. | वेनजुएला | 35,700 |
| 11. | नाईजीरिया | 24,700 |
| 12. | मैक्सिको | 22,500 |
| 13. | इंगलैंड | 22,000 |
| 14. | इंडोनेशिया | 13,900 |
| 15. | तटस्थ जोन@ | 9,200 |
| 16. | अलजीरिया | 8,000 |
| 17. | कनाडा | 8,100 |
| 18. | नारवे | 8,000 |
| 19. | ब्रुनइ-मलेशिया | 5,800 |
| 20. | कातार | 5,200 |
| 21. | इजिप्ट (मिश्र) | 4,700 |
| 22. | भारत | 4,000 |
| 23. | सीरिया | 3,400 |
| 24. | ओमान | 3,400 |
| 25. | अर्जेनटीना | 3,300 |
| | इन 25 राष्ट्रों का योग | 8,45,000 |

नोट : तुलना के लिए 1977 में संसार में तेल का प्रयोग 25,000 लाख टन था.

@ ये दो पड़ोसी तटस्थ जोन है : एक तो ईराक और सउदी अरबिया की सीमा पर और दूसरा कुवैत और सउदी अरबिया की सीमा पर है.

## विश्व कोयला संचय

*(लाख टन में)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अमेरिका | 11,32,300 |
| 2. | चीन | 9,88,830 |
| 3. | सोवियत यूनियन | 8,29,000 |
| 4. | इंगलैंड | 4,50,000 |
| 5. | भारत | 3,33,450 |
| 6. | दक्षिण अफ्रीका | 2,69,030 |
| 7. | एफ. आर. डी. | 2,39,190 |
| 8. | पोलेंड | 2,08 000 |
| 9. | कनाडा | 87,080 |
| 10. | ब्राजील | 25,100 |
| 11. | चेकोस्लोवाकिया | 24,930 |
| 12. | स्वाजीलैंड | 18,200 |
| 13. | नैदरलैंड | 14,300 |
| 14. | रोडेशिया | 13,900 |
| 15. | जापान | 10,000 |
| 16. | वेनजुएला | 9,780 |
| 17. | मैक्सिको | 8,750 |
| 18. | बंगलादेश | 5,170 |
| 19. | बोटस्वाना | 5,100 |
| 20. | फ्रांस | 4,270 |
| 21. | कोलम्बिया | 3,970 |
| 22. | दक्षिण कोरिया | 3,860 |
| 23. | स्पेन | 3,220 |
| 24. | पी. डी. आर. कोरिया | 3,000 |
| 25. | हंगरी | 2,230 |
| 26. | ईरान | 1,930 |
| 27. | टर्की | 1,340 |
| 28. | बेल्जियम | 1,270 |
| 29. | पीरू | 1,050 |
| 30. | जी. डी. आर. | 1,000 |

विश्व का योग : 1 जनवरी 1979 को 49,02,720 लाख टन. विश्व के उपभोग के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं.

नोट : 1978 में चीन का तेल उत्पादन 1,040 लाख टन था (2.08 बैरल प्रति

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

## महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

| राज्य/केंद्र | 1980 | | |
|---|---|---|---|
| | मार्च | अप्र. | मई |
| **बिहार** | | | |
| जमशेदपुर | 358 | 367 | 375 |
| झारिया | 357 | 358 | 356 |
| कोडर्मा | 399 | 397 | 399 |
| मोंघाइर | 394 | 397 | 406 |
| नोआमुंडी | 362 | 362 | 368 |
| **गुजरात** | | | |
| अहमदाबाद | 359 | 360 | 365 |
| भाव नगर | 387 | 388 | 395 |
| **हरियाणा** | | | |
| यमुना नगर | 405 | 403 | 418 |
| **जम्मू व काश्मीर** | | | |
| श्रीनगर | 367 | 387 | 396 |
| **मध्य प्रदेश** | | | |
| बालाघाट | 394 | 400 | 405 |
| भोपाल | 374 | 374 | 377 |
| ग्वालियर | 392 | 393 | 408 |
| इंदौर | 387 | 390 | 393 |
| **महाराष्ट्र** | | | |
| बंबई | 375 | 381 | 385 |
| नागपुर | 363 | 365 | 377 |
| शोलापुर | 383 | 383 | 384 |
| **पंजाब** | | | |
| अमृतसर | 391 | 393 | 388 |
| **राजस्थान** | | | |
| अजमेर | 385 | 388 | 401 |
| जयपुर | 392 | 395 | 411 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| कानपुर | 370 | 374 | 381 |
| सहारनपुर | 383 | 383 | 388 |
| वाराणसी | 432 | 433 | 438 |
| **पश्चिम बंगाल** | | | |
| आसन सोल | 387 | 387 | 390 |
| कलकत्ता | 356 | 362 | 371 |
| दार्जीलिंग | 312 | 311 | 321 |
| हावड़ा | 347 | 347 | 353 |
| जलपाइगुरी | 312 | 313 | 323 |
| रानीगंज | 373 | 377 | 380 |
| **दिल्ली** | 398 | 401 | 407 |
| **भारत** | 373 | 375 | 382 |

# सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक सितंबर में

**सी.** आई. टी. यू. की जनरल काउंसिल की बैठक 11-14 सितंबर को कन्नानोर, केरल में होगी. यह बैठक 11 सितंबर को शाम 4 बजे शुरू होगी.

बैठक की शुरूआत सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे के भाषण से होगी. सीटू महासचिव पी. राममूर्ति जनरल रिपोर्ट पेश करेंगे जिसके बाद सीटू सचिव एम. के. पंधे कार्य व संगठन की रिपोर्ट पेश करेंगे. 1979 का लेखा-जोखा भी इस बैठक में दिया जाएगा.

इन रिपोर्ट पर बहस के अलावा, जनरल काउंसिल में महिला श्रमिकों को अधिक रोजगार देने के नाम पर संरक्षण कानून में सुधार के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा. इस बैठक में, अक्तूबर में, अखिल भारतीय श्रमिक महिला कानफ्रेंस आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा.

जनरल काउंसिल में, पिछली वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद से आए संबद्धता के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा और सीटू की चौथी कानफ्रेंस में जनरल काउंसिल के जो स्थान खाली रखे गये थे, भरे जाएंगे.

मजदूर वर्ग व लोगों की समस्याओं को लेकर कई प्रस्ताव भी इस जनरल काउंसिल में स्वीकार किये जाएंगे.

सीटू की जनरल काउंसिल के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बैठक में अवश्य भाग लें. स्वागत समिति सदस्यों के चार दिन के खाने के लिए 120 रुपये लेगी. खाने की सुविधाएं सिर्फ 11 से 14 सितंबर तक होंगी लेकिन रहने की सुविधाएं 10 और 15 सितंबर को भी उपलब्ध होंगी. स्वागत समिति का पता है : कन्नानोर डिस्ट्रिक्ट कमेटी आफ सी. आई. टी. यू., ट्रेड यूनियन हाऊस, कन्नानोर, केरल.

उद्योग-अनुसार बैठकें 11 सितंबर को होगी जिसके सर्कुलर उन उद्योगों की यूनियनों को अलग से भेजे जाएंगे. इन उद्योग-अनुसार बैठकों में आने वाले कामरेडों को अपने खाने का इंतजाम खुद करना होगा.

जो कामरेड अपनी वापसी का टिकट बुक करवाना चाहते हो, वे टिकट का भाड़ा और टिकट संबंधी अन्य जानकारियां स्वागत समिति को 15 अगस्त तक भेज दें.

जो सदस्य, जनरल काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पेश करना चाहते है, वे 15 अगस्त तक अपने ड्राफ्ट सीटू केंद्र भेज दें जिससे वे समय पर अन्य सदस्यों को दिये जा सकें.

नई यूनियनों के आवेदन-पत्र 25 अगस्त तक सीटू केंद्र पहुंच जाने चाहिए.

सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक 2 बजे उसी स्थान पर होगी.

असम

# जनवादी मूल्यों की रक्षा करो

**प्र**मुख कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, अध्यापकों, सांस्कृतिक संगठनों तथा जनवादी व ट्रेड यूनियन संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक गोहाटी में 17 जून को हुई. बैठक में राज्य की गंभीर हालतों को देखते हुए व इन हालतों के संदर्भ में जनतांत्रिक मूल्यों व जनवादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय किया गया.

इस अवसर पर अपील जारी की गई जिसमें इन संस्थाओं के 80 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं. अपील में कहा गया है: "राज्य भर में खतरनाक जनतन्त्र-विरोधी शक्तियां सिर उठा रही हैं. कई व्यक्तियों व संस्थाओं को, जो स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, अपमानित किया जा रहा है तथा उन पर हमले हो रहे हैं... सारा वातावरण झूठी खबरों, अफवाहों व शरारतपूर्ण प्रचार से भर गया है" अपील में कहा गया है कि असम समस्या का समाधान तब तक नहीं खोजा जा सकता जब तक विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने व आपसी विचार विमर्श करने के लिए सही वातावरण नहीं बनाया जाता.

अपील में असम की जनवादी परंपरा रखने वाली सभी सस्थाओं व संगठनों व आम जनता को आह्वान किया गया है कि वे जनतांत्रिक मूल्यों व जनवाद की रक्षा के लिए साहसपूर्वक सामने आएं, वे राष्ट्रीयता, धर्म अथवा भाषा के नाम पर जनता को बंटने न दें व जनवादी अवाम की एकता को मजबूत करें. केवल इस एकता से ही जनतंत्र के दुश्मनों को **परास्त किया** जा सकता है.

## त्रिपुरा फंड

[पृष्ठ दो से आगे]

सीटू सेंटर, 1000; वरली सीटू सेंटर, 1000; वूलन मि. का. यू. (ठाना), 1000; लाल बावटा यो. एंड बेकरी म. यू. 500; ओटीस एंप. यू., 500; लोखंडी जथा एंड ज. का. यू., 500; प्रेस एंप. यू., 500;

## बिहार

गलास एंड पोट. का. यू. माधोपुर, 100; 11 वीं कां. आफ इंड रेल कोल ऐश ट्रांश. म. यू., 668.04; और डालमिया नगर व. यू., 100;


**सीटू प्रकाशन**

**कोयला खदानों में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का चेहरा बेनकाब**

*कीमत : 40 पैसे*

लिखें :

**सीटू कार्यालय**

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-10001

# केनरा बैंक कर्मचारियों का लंबा संघर्ष : गौरवशाली समझौता

केनरा बैंक का नौ महीने लंबा आंदोलन 24 जुलाई को नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हुए केनरा बैंक स्टाफ यूनियन द्वारा हुए गौरवमयी समझौते के बाद अंततः सफल हुआ.

समझौते के मुख्य तथ्य थे :
(1) बिना किसी पूर्वशर्त के मुअत्तिली आदेश तथा 12 यूनियन कार्यकर्त्ताओं को दी गई चार्ज शीटों की वापसी. (2) आंदोलन को रोकने के लिए बैंक द्वारा किए गए मुकदमों की वापसी. (3) व्यक्तिगत रूप में कर्मचारियों की शिकायतों तथा झगड़ों को सुलझाने के लिए एक द्विपक्षीय मंच की स्थापना. (4) अंतिम समझौते से पहले सामूहिक सौदेबाजी के लिए यूनियन को आवाज. इनके अतिरिक्त दंड देने की नीयत से किए गए तबादलों तथा गैर कानूनी तौर पर वेतन काटने के मामलों के खात्में सहित अन्य मांगे भी आपस में सुलझा ली गई.

प्रबंधकों द्वारा दो साल पहले द्विपक्षीय मंच को खत्म करने तथा यूनियन से आपसी बातचीत न करने, केनरा बैंक में ए. आइ. बी. ई. ए. यूनियन द्वारा अदालती कार्रवाई करने तथा उसके द्वारा बातचीत व समझौते में रुकावट आने की वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया था. इस मामले में किया गया. मुकदमा बाद में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा फिर भी ए. आइ. बी. ई. ए. यूनियन तथा प्रबंधक मिलकर स्टाफ यूनियन को खत्म करने पर तुले थे. उसके बाद से कर्मचारियों को प्रत्येक मांग पर ए. आइ. बी. ई ए. तथा प्रबंधकों की मंडली ने पक्षपाती समझौते बनाकर कर्मचारियों पर लादने जारी रखें.

स्टाफ यूनियन ने न केवल ए. आइ. बी. ई. ए यूनियन व प्रबंधकों की सांठ गांठ को बेनकाब किया बल्कि कर्मचारियों की मांगों को रूप देने के लिए तथा उनके हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर प्रदर्शन भी किए. कर्मचारियों के एकताबद्ध विरोध से सबक सीखने की बजाय ए. आइ. बी. ई. ए. यूनियन ने इस सांठ गांठ को और अधिक मजबूत बनाया तथा कर्मचारियों की यूनियन को तहस नहस करने का षड्यंक्ष भी रचा. यह इनके षड्यंत्र का ही नतीजा था कि स्टाफ यूनियन कार्यकर्त्ताओं को झूठे आरोपों के तहत चार्जशीट दी गई व मुअत्तिल कर दिया गया और साथ ही उनपर फौजदारी के मुकदमें भी चलाए गए. जागरुक सदस्यों को गैरकानूनी तौर पर वेतन काटने तथा दंड देने की नीयत से तबादलों को भी सहना पड़ा.

सदस्यों को यूनियन से दूर करने की हर जरूरी कोशिश की गई मगर अधिक से अधिक कर्मचारी यूनियन में सम्मिलित होते गए और यहां तक कि यूनियन में शामिल होने वाले कुछ सदस्य तो ए. आइ. बी. ई. ए. यूनियन छोड़कर आए थे. प्रबंधकों के हर हमले का सामना यूनियन के सदस्यों ने दृढ़ता से किया.

सदस्यों की एकता और उनके दृढ़ निश्चय के कारण ही आंदोलन का अंत इस गौरवमयी समझौते में हुआ. इससे कर्मचारियों को केनरा बैंक स्टाफ यूनियन के झंडे तले और अधिक एकताबद्ध होने की प्रेरणा मिलती है.

ए. आइ. बी. ई. ए. यूनियन तथा प्रबंधकों की सांठ गांठ की चरम सीमा का यहां जिक्र करना सही होगा. ए. आइ. बी. ई. ए. के नेतृत्व ने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व के बढ़ने की खिलाफत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. लेकिन औद्योगिक स्तर पर विशेष भत्ते पाने वाले कर्मचारियों ने इसे केनरा बैंक के एक हस्ताक्षरकृत समझौते में खामोशी से स्वीकार किया है. दिखाने के तौर पर ऐसा है पर असलियत में ए. आइ. बी. ई. ए. इसके विपरीत काम करती है. इस विश्वासघात के विरोध में केनरा बैंक के कर्मचारी दोबारा एकजुट हुए हैं तथा हर शाखा अनुसार दिए जा रहे ज्ञापनों में ऐसे समझौतों का विरोध किया जा रहा है.

यह साधारण एकताबद्ध विरोध इतना प्रभावशाली रहा कि प्रबंधकों ने अपने गुप्त आदेश में अधिकारियों को ए. आइ. बी. ई. ए. यूनियन में हुए समझौते को अमल में न लाने को कहा है.

इस आंदोलन से सही सबक सीखने वाले कर्मचारी अपने हितों की रक्षा के लिए ए. आइ. बी. ई. ए. तथा प्रबंधकों की इस सांठ गांठ का खात्मा करके ही रहेंगे. साथ ही केनरा बैंक स्टाफ यूनियन ट्रेड यूनियन के हित में इस बढ़ते आंदोलन का मार्ग दर्शन करती रहेगी,

# इंस्ट्रूमैंटेशन कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल

इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड (कोटा) तथा देश भर के 19 केंद्रों के कर्मचारी 10 मार्च से अपने 5-सूत्री मांगपत्र के समर्थन में हड़ताल पर हैं प्रबंधक अब तक हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए कोई सुझाव लेकर सामने नहीं आए हैं. वास्तव में समझौता करने के प्रयत्नों के बजाय वे हड़ताल तोड़ने के उद्देश्य से ऐसे नए व्यक्तियों की भर्ती कर रहे हैं जिसका इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है. ट्यूटीकार्न परियोजा में गैर-अनुभवी व्यक्तियों की मदद से काम करवाने का परिणाम यह हुआ कि यह परियोजना ही ठप्प हो गई जिस कारण आम जनता को काफी तकलीफ उठानी पड़ी.

कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र में मुख्य मांगे हैं—अनियमित व अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाना, विकिट-माइजेशन व गलत तरीकों का अंत, वेतन व महंगाई भत्ते में संशोधन आदि. यह मांगपत्र दिसंबर 1979 में पेश किया गया था. प्रबंधकों ने इसका जवाब दमन से दिया. आल इंडिया इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट्स एम्पलाईज यूनियन को 23 फरवरी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा. 28 फरवरी को सभी केंद्रों पर सांकेतिक हड़ताल रही व 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ हुई. 7 अप्रैल से 5 जून तक कोटा हैडक्वार्टर्स में क्रमिक भूख हड़ताल चली व इसके बाद आमरण अनशन आरंभ हुआ. 10 जून को पुलिस की सहायता लेकर भूख हड़तालियों को गिरफ्तार कर लिया गया व उनके टैंट व अन्य सामान उखाड़कर फेंक दिया गया. हड़ताल के कारण इस संस्थान की सारी परियोजनाएं बंद हो गई है. समझौता करने के यूनियन के सभी प्रस्तावों को नकार दिया गया है. अब यूनियन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से अपील की है कि वे इस मामले में दिलचस्पी दिखाएं व हड़ताल को समाप्त करवाने में अपनी भूमिका निभाएं हड़ताल को अप्रत्याशित सफलता मिल रही है.

# इस्पात मजदूरों का विरोध दिवस : 12 अगस्त

हाल ही के वेतन समझौते पर दस्तखत करने के बाद सीटू की इस्पात को-ओर्डिनेशन कमेटी ने 6 जुलाई को कलकत्ता में मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई. बामापद मुखर्जी ने सभा की अध्यक्षता की. सभा में भाग लेने वाले सदस्यों ने मजदूरों में अशांति पैदा करने वाले विषयों की एक रपट पेश की. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

इस्पात उद्योग की स्थायी किस्म की नौकरियों में ठेका व्यवस्था का खात्मा करने में ठेका मजदूरों की समस्याएं तथा प्रबंधकों की ओर से साहसिक कदम उठाने में असफलता.

छुट्टी यात्रा सुविधा की समस्या तथा उसके उचित भुगतान में प्रबंधकों द्वारा डाली जाने वाली अड़चनों की समस्या.

इस्पात मजदूरो में स्थिरता के प्रश्न तथा भिलाई में इंटक यूनियन द्वारा किए गए एक विशेष वेतनमान के तहत दस वर्षों तक काम करने के समझौते को लेकर प्रचालित असंतोष. यह समझौता अपनी निष्क्रियता के कारण बहुत से इस्पात प्लांटों में मजदूरों की आलोचना का केन्द्र बना रहा. मजदूर एक वेतन-मान के तहत मात्र 5 वर्ष तक काम करने की स्थिरता की मांग कर रहे थे.

पिछले वेतन समझौते की असंगतियों का प्रश्न जिन्हें अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझाया गया है तथा इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान ढूंढ निकालने में प्रबंधकों की विलम्बकारी नीति.

तीन साल पहले इस्पात मंत्रालय द्वारा बनाए गए अध्ययन दल की तहकीकातों को इस्पात प्रबंधकों ने अभी तक लागू नहीं किया है. मजदूर यह मांग कर रहे हैं कि इस अध्ययन दल की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए.

इस्पात उद्योग में मजदूर यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता दिए जाने का प्रश्न भी काफी अर्से से सुलझ नहीं पाया है. दुर्गापुर और एलोय इस्पात प्लांट को छोड़कर प्रबंधक मात्र अपनी पसंद की वर्क्स कमेटी और अन्य बहुत सी कमेटियों में चुनाव के प्रश्न को भी प्रबंधकों ने गंभीरता से नहीं लिया.

मंहगाई की पूरी भरपाई की मौजूदा दर के प्रश्न पर मजदूर अभी तक अप्रसन्न हैं. इस समय उपभोक्ता कीमत सूचकांक में सिर्फ 1.30 रुपये प्रति बिन्दु बढ़ोतरी के हिसाब से दिए जाते हैं जबकि मजदूर पूरी भरपाई की मांग कर रहे हैं.

यही कारण है कि कोओर्डिनेशन कमेटी ने सभी इस्पात इकाइयों द्वारा पूरे देश में विरोध दिवस मनाने का निश्चय किया है जिससे कि इस्पात अधिकारियों का ध्यान मजदूरों में मौजूद असंतोष की ओर आकर्षित किया जा सके. यह निश्चय किया गया कि प्रबंधकों के रवैये की अलोचलना करने के लिए 12 अगस्त को विरोध-दिवस मनाया जाए.

साथ ही यह भी फैसला किया गया कि इस्पात मजदूरों की उचित मांगों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हिन्दी में 7000 तथा. बंगाली में 9000 पुस्तिकाएं छापी जाएं.

सभा में इस्पात मजदूरों को आसाम और त्रिपुरा में साम्राज्यवादी एजेन्सियों तथा उनके पिट्ठुओं द्वारा रची गई साजिशों के बारे में जानकारी देने का भी निश्चय किया गया. साथ ही सभी यूनियनों का त्रिपुरा अनुदान राशि में सहयोग देना भी निश्चित हुआ.

बैठक में सदस्यता अभियान चलाने तथा सीटू संगठन को इस्पात मजदूरों के बीच मजबूत बनाने का फैसला किया गया.

साथ ही वर्ष की समाप्ति से पहले दुर्गापुर में आल इंडिया स्टील वर्कर्स कांफ्रेंस करने का भी निश्चय किया गया. निश्चित तारीखें सीटू केन्द्र से बातचीत के बाद ही तय की जाएंगी.

ओआर्डिनेशन कमेटी की अगली बैठक सितम्बर 1980 के अंतिम सप्ताह में होनी निश्चित हुई.

## पश्चिम बंगाल समाचार

# हिंदुस्तान गलास फैक्ट्री में तालाबंदी

असनसोल की हिंदुस्तान गलास फैक्ट्री के लगभग 1500 मजदूर, प्रबंधकों द्वारा जून के पहले सप्ताह से घोषित की गई तालाबंदी के कारण भुखमरी से पीड़ित हैं. प्रबंधकों के बेइमानी करने के इरादों के कारण यह लाभ कमाने वाली और विदेशी मुद्रा इकट्ठा करने वाली फैक्ट्री अब बेइमान व मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने वाली बन गई है. कुछ समय पहले इसके अपने एक ब्रिटिश सहायक, पिलकिंगटन ब्रदर्स ने गैरकानूनी ढंग से अपने 50 प्रतिशत शेयर थापर को दे दिये थे. प्रबंधकों द्वारा घोषित इस गैरकानूनी तालाबंदी और उनके द्वारा अपनाये गये गलत तरीकों के खिलाफ मजदूर एकजुट होकर संघर्षरत हैं. पिछली 6 जून को उन्होंने एक मांगपत्र वाणिज्य मंत्री को पेश किया था, जिसमें गैरकानूनी ढंग से थापरों को शेयर देने पर पाबंदी लगाने और फैक्ट्री अपने हाथों में लेने की मांग की गई है.

# सी. ई. एस सी. कर्मचारियों ने मांग दिवस मनाया

कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन के लगभग 11,500 मजदूरों ने, 11 जुलाई को चार यूनियनों की को-आर्डिनेशन कमेटी जिसमें मजदूर यूनियन (सीटू) भी शामिल है, के नेतृत्व में मांग दिवस मनाया. पिछले नौ महीनों से लगातार प्रबंधक सितंबर 79 को मजदूरों द्वारा पेश किये गये मांगपत्र पर बातचीत करने के लिए मजदूर विरोधी और अड़ियल रवैया अपनाये हुए हैं. प्रबंधकों द्वारा समझौता करवाने की मजदूर विरोधी शर्तों के कारण त्रिपक्षीय वर्त्तायें असफल रहीं. इसके विरोध में, 27 जून को मजदूरों व कर्मचारियों ने 2 घंटे के लिए काम बंद कर दिया. इस बीच, मजदूरों व कर्मचारियों के विरोध के बावजूद भी प्रबंधक कई विभागों में कम्प्यूटरों का इस्तेमाल करने का प्रयत्न कर रहे हैं. 11 जुलाई को हुई मजदूरों की एक रैली में उन्होंने मांगपत्र पर तुरंत बातचीत द्वारा हल करने की मांग की है.

# बेनी इंजीनियरिंग में ग्यारह माह से तालाबंदी

कलकत्ता के पास स्थिति बेनी इंजीनियरिंग फैक्ट्री के प्रबंधकों ने 11 महीने से तालाबंदी कर रखी है. मालिकों ने 31 जुलाई 79 को आर्थिक कठिनाइयों के बहाने तालाबंदी की थी जबकि तालाबंदी करने के समय उनके पास रेल, रक्षा तक अन्य कई सरकारी आर्डर थे. लगभग 1400 मजदूरों व कर्मचारियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तालाबंदी से दो महीने पहले के भी वेतन नहीं दिये गये और मजदूरों व कर्मचारियों के ई. एस. आई., पी. एफ., ग्रेच्युटी तथा अन्य लाभ जो कई लाख रुपयों में हैं, उनका प्रबंधकों द्वारा गलत प्रयोग किया गया है. मजदूर यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल तथा महासचिव शांति घटक ने एक बयान में तालाबंदी को तुरंत खत्म करने की मांग की है तथा उस क्षेत्र के अन्य मजदूर संगठनों को जिन्होंने संघर्षरत मजदूरों को बिरादराना समर्थन तथा सहायता दी है, को धन्यवाद दिया है.

# साढ़े चार महीने के बाद एस. आई. जी. सी. ओ. एल. खुली

कलकत्ता के पास स्थित साईंटीफिक इंडियन गलास कंपनी की फैक्ट्री साढ़े चार महीने बंद रहने के बाद 16 जून को, राज्य के श्रम-मंत्री के चेंबर में 10 जून को हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के बाद खुली. समझौते के अंदर, प्रबंधकों ने, सभी मजदूरों को वापस काम पर लेना, बकाया वेतन व ओवर-टाइम देना, ई. एस. आई. और पी. एफ. का बकाया चुकाना तथा प्रत्येक मजदूर को 150 रुपये अग्रिम भुगतान करना आदि स्वीकार किया है.

फैक्ट्री के पिछले मालिकान ने केवल फैक्ट्री का गलत प्रबंध ही नहीं किया बल्कि मजदूरों के साथ किये गये समझौते को भी लागू करने से इंकार कर दिया. इस पर उन्होंने 28 जनवरी को तालाबंदी कर दी और फर्टीलाइजर को फैक्ट्री शेड में इकट्ठा करने की कोशिश की. जब उनके प्रयत्न मजदूरों द्वारा नाकामयाब कर दिये गये तब उन्होंने कंपनी नए प्रबंधकों को सौंप दी.

# अंबिका फैक्ट्री के मजदूरों की जीत

अंबिका प्रोसेसिंग फैक्ट्री के मजदूर, उत्तरी कलकत्ता पावरलूम एंड प्रोसेसिंग मजदूर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में 1979 में हुए समझौते को लागू करवाने के लिए लगातार संघर्ष पर थे. उन्होंने रोजाना सात दिनों तक दो घंटे तक काम बंद आदि ट्रेड यूनियन गतिविधियां आयोजित की जिसके फलस्वरूप, प्रबंधकों को, 1979 के समझौते को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे मजदूरों को 1980 के वेतन में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी मिली. उत्तरी कलकत्ता व राज्य के अन्य भागों के 50 हजार से भी ज्यादा पावरलूम-मजदूर जिन्हें अभी तक यह बढ़ोतरी नहीं दी गई थी, इस जीत से प्रोत्साहित हुए हैं.

# दार्जीलिंग चाय मजदूरों ने ऐतिहासिक दिवस मनाया

25 जून को दार्जीलिंग जिला की चाय कमान मजदूर यूनियन ने, दार्जीलिंग जिला में 'मार्ग्रेट की होप टी इस्टेट'. में जिसमें जून 1955 में पुलिस द्वारा क्रूरता से गोली चलाने से 6 मजदूरों की मृत्यु हुई थी, के 25 साल मनाये. इस अवसर पर एक रैली हुई जिसमें लगभग 12,000 लोगों ने भाग लिया. इससे पहले वो एक जलूस की शक्ल में आये थे. भारी वर्षा के बावजूद, प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा कार्यक्रम को विफल करने की धमकियों को तोड़ कर ये लोग दूर-दूर से आये थे.

इस रैली की अध्यक्षता करते हुए रतनलाल ब्राह्मण ने लोगों को इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक एकता को मजबूत बनाने के लिए कहा. इनके अलावा रैली को सांसद

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

# अखिल भारतीय जूट सम्मेलन की तैयारियां

जूट मजदूरों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के लिए उनका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कानपुर में 27 और 28 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अखिल भारतीय जूट मजदूर सम्मेलन की संगठन कमेटी के संयोजक कमल सरकार ने 19 और 20 जुलाई को कानपुर क्षेत्र का दौरा किया और साथ ही सम्मेलन का बंदोबस्त करने के लिए मजदूरों व कार्यकर्ताओं की कई बैठकें बुलवाईं.

19 जुलाई को जे. के. रेयन मजदूरों की एक रैली में बोलते हुए कमल सरकार ने तथाकथित बिजली की जरूरत के कारण 27 अगस्त 1979 से बंद मिल के खिलाफ एकताबद्ध मजदूरों के गौरवशाली संघर्ष की तारीफ की. उन्होंने मजदूरों से राज्य में वामपंथी ताकतों को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपना संघर्ष पश्चिम बंगाल के मजदूरों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ले चलने की अपील की. सभा की अध्यक्षता बंसीधर तिवारी ने की.

जूट सम्मेलन से संबंधित सीटू के कार्यकर्ताओं की एक बैठक 20 जुलाई को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता श्यामसुन्दर ने की. बैठक में यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम के लगभग 200 प्रतिनिधि तथा उत्तरप्रदेश के लगभग 50 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे. कुछ बिरादराना प्रतिनिधि भी सम्मेलन में उपस्थित होंगे, सम्मेलन की अध्यक्षता सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे करेंगे.

सीटू सचिव कमल सरकार ने कहा कि जूट सामंत एक हो कर जूट मजदूरों के संघर्ष के खिलाफ लड़ते हैं इसलिए जूट मजदूरों के जोरदार अखिल भारतीय संगठन की मौजूदगी की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अखिल भारतीय संगठन सिर्फ जूट मजदूरों की दिन प्रतिदिन की मुश्किलात से ही संघर्ष नहीं करेगा बल्कि यह पूंजीवादी व उसकी रहनुमा ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए मजदूरों में वर्ग चेतना जगाने की भी कोशिश करेगा.

कामरेडों ने इस बात का आश्वासन दिया कि सम्मेलन को सफल बनाने में वे हर कोशिश करेंगे. वक्ताओं ने कहा कि कानपुर में इस सम्मेलन के आयोजन से राज्य विशेष रूप में कानपुर के ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रोत्साहन मिलेगा.

इस अवसर पर टेनरी और फुटवियर कार्पोरेशन के मजदूरों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी बुलाई गई. कमल सरकार ने इन मजदूरों को नए वेतनमानों तथा अन्य मांगों के लिए जारी उनके संघर्ष के लिए बधाई दी. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मजदूरों के सफल एकताबद्ध संघर्ष पर जोर दिया. उन्होंने मजदूरों व संघर्ष की एकता पर बल दिया और बताया कि यह सिद्धांत पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है.

## पश्चिम बंगाल समाचार

[पृष्ठ दस से आगे]

आनंद पाठक व एस. पी. लेपचा, दावा लामा, डी. आर. लामा, जेठीमाया राय, टी. एम. राय और पश्चिम बंगाल के यातायात मंत्री एम. अमीन ने संबोधित किया. अमीन ने, दार्जीलिंग में विपक्ष द्वारा, इस पहाड़ी क्षेत्र में यातायात की सुविधाएं व सरकार की नीतियों को लागू करवाने में खड़ी होने वाली बाधाओं का खासतौर से जिक्र किया. सीटू सचिव, कमल सरकार ने आक्रमणकारियों के आक्रमणों का जवाब देने के लिए मजदूर वर्ग की एकता के महत्व पर और आर्थिक संघर्ष को जनवादी अधिकारों की रक्षा व उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष के साथ जोड़ने पर जोर दिया.

## सीटू यूनियन की जीत

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन (सीटू) के हाल ही में हुए स्पोर्ट्स काउंसिल के चुनाव जीत गई. यूनियन ने जी. एस., आउटडोर सेक्रेटरी, इंडोर सेक्रेटरी और ट्रेजरर की जगह जीती जबकि इंटक की यूनियन को केवल कल्चरल सेक्रेटरी की जगह ही मिली. कलकत्ता एच. एच. सी. एल. के मजदूर, पहले से ही स्पोर्ट्स काउंसिल के गठन व उसके चुनावों की मांग करते आ रहे थे.

## उड़ीसा सीटू की बैठक

सीटू की उड़ीसा राज्य कमेटी की एक बैठक भुवनेश्वर में 21 जुलाई को हुई. इसकी अध्यक्षता शिवाजी पटनायक ने की. बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों तथा राज्य की संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की गई.

दिनभर की चर्चा के बाद राज्य कमेटी ने कीमतों पर बढ़ोतरी के खिलाफ आसाम व त्रिपुरा के आंदोलनों, त्रिपुरा में उपद्रव के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा को काले अध्यादेशों के खिलाफ तथा अन्य विषयों पर कई प्रस्ताव पास किए. कमेटी ने कालटा खदानों में पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट प्रबंधकों के सीटू संगठन को कुचलने की कोशिश के रवैये की भरसक निंदा की.

बैठक में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 'सीटू मास' मनाने का आह्वान किया गया. इसके तहत सीटू के विकास तथा जनता को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों और सीटू के सदस्य बनाने आदि का अभियान छेड़ा जाएगा. साथ ही कमेटी ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य खुदमुख्तार यूनियनों को एकजुट होकर मेहनतकश जनता पर हो रहे बुर्जुआ सामंतीय सरकार के अवश्यंभावी हमले के खिलाफ संघर्ष किए जाने पर जोर दिया.

## रेल समाचार

# लोको कर्मियों के वेतनमानों में संशोधन

समझा जाता है कि बातचीत के कई दौर के बाद लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वेतनमानों में संशोधन हासिल करने में कामयाब हो गई है और इससे 82,429 कर्मियों में से 80 हजार से भी ज्यादा को फायदा पहुंचेगा. रेलकर्मियों के कुल वेतन संशोधन न होने तक, रेलवे बोर्ड ने लोकोकर्मियों के केडर की पुनर्रचना का प्रस्ताव रखा था जो कुछ सुधार के बाद मान लिया गया.

ए. आइ. एल. आर. एस. ए. के महासचिव एस. के. धर के अनुसार ड्राइवरों के 5 वेतनमानों को 4 वेतनमानों में बदल दिया जाएगा कोचिंग ड्राइवर ग्रे-I व ग्रे-II तथा गुड्स ड्राइवर ग्रे-I व ग्रे-II. यह एसोसिएशन की राय के खिलाफ है क्योंकि इसके अनुसार ड्राइवरों के दो ही वेतनमान होने चाहिए: कोचिंग व गुड्स. रेलवे बोर्ड ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को मान लिया और इसके तहत फायरमैन 'ए' व फायरमैन 'बी' का एक ही ग्रेड होगा जो फायरमैन ग्रे-I कहलाएगा. ये कुछ मूल बातें हैं जिसके लिए एसोसिएशन संघर्ष कर रही थी.

वेतनमानों की यह पुनर्रचना लोको रनिंग स्टाफ के सभी केडरों में स्थिरता को खत्म करने में सहायक होगी. इससे उनका रनिंग अलाउंस भी बढ़ेगा क्योंकि कमेटी ने यह भत्ता पुराने वेतनमानों के आधार पर तय किया है इस लिए इस भत्ते को बढ़ाने के लिए संशोधन की जरूरत होगी.

रनिंग अलाउंस पर बातचीत शुरू हो गई है. लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा दिए गए दो ज्ञापनों के हर पहलू को रेलवे बोर्ड नकार रहा है इसलिए बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है.

# उत्तर रेलवे लोको कर्मियों ने चेतावनी दी

ए. आइ एल. आर. एस. ए. के अध्यक्ष एस. आर. बग्गा व क्षेत्रीय सचिव (उत्तरी क्षेत्र) शाम लाल ने रेलवे के केंद्रीय राज्य मंत्री के नाम लिखे एक पत्र में बताया कि बातचीत के दौरान दिए गए वादों के बावजूद विक्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है व 221 लोको कर्मचारियों को अपने बचाव में कुछ कहने को मौका दिए बिना ही सजाएं दी जा रही हैं.

पत्र में यह भी बताया गया कि पुलिस द्वारा दमन की कार्रवाई लगातार चल रही है. इसका प्रमाण है 11 जुलाई को भटिंडा में हुई गिरफ्तारी व नई दिल्ली जी. आर. पी. एस. में पुलिस द्वारा किशन लाल शंटर की पिटाई. इन कारणों से एल. आर. एस. ए. के क्षेत्रीय सचिव को 7 जुलाई को रेलवे अधिकारियों की चेतावनी देनी पड़ी कि यदि एक पखवाड़े के भीतर इन समस्याओं का समाधान न किया गया तो लोको कर्मचारियों को पुनः आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.

21 जुलाई को रेलवे मंत्रालय के कार्यालय के हस्तक्षेप पर हालात में कुछ सुधार हुआ है. अब एसोसिएशन के महासचिव उत्तरी रेलवे के जनरल मैनेजर व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से इन मसलों पर बातचीत करेंगे जिसके बाद क्षेत्रीय एल. आर. एस. ए. हालात पर पुनर्विचार करेगा.

# कैरेज व वैगन कर्मचारियों का प्रदर्शन

आल इंडिया कैरेज एंड वैगन स्टाफ काउंसिल की वार्षिक बैठक नई दिल्ली के बैडमिंटन हाल में 3 व 4 जून को हुई. काउंसिल के भूतपूर्व खजांची इसके महासचिव चुने गए. इस अवसर पर इस विभाग के 200 कर्मचारी दिल्ली आए व उन्होंने बोट क्लब पर आम सभा की. 5 जून को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से इस मांग पत्र पर बातचीत की गई. ऐसा समझा जाता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने काउंसिल को बताया है कि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा.

# बैठक व सम्मेलन

इंडियन रेलवेज कोल, ऐश, एंड ट्रांशिपमैंट हैंडलिंग मजदूर यूनियन की वार्षिक बैठक 4 व 6 जुलाई को कटिहार में हुई. सीटू की बिहार राज्य कमेटी के महासचिव चंडी प्रसाद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. 40 महिलाओं सहित 600 डेलिगेटों ने बैठक में हिस्सा लिया. बठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सत्य नारायण सरकार ने की. संसद सदस्य समर मुखर्जी ने 5 जुलाई को प्रतिनिधि सभा में तथा बैठक के बाद हुए खुले अधिवेशन में भाषण दिया. प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा की जनता की सहायता के लिए 668 रुपये एकत्रित किए व इस धन को भेजने के लिए समर मुखर्जी को दिया. सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने भी प्रतिनिधि सभा व खुले अधिवेशन दोनों स्थानों पर मजदूरों को संबोधित किया.

इप्टा (कलकत्ता) की कलाकार यूनिट न केवल दोनों दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए बल्कि कटिहार की सड़कों पर त्रिपुरा की जनता की सहायता के लिए धन एकत्रिक किया.

संसद सदस्य समर मुखर्जी ने कटिहार के लोको शेड का दौरा किया व वहां की समस्याओं को समझा. बाद में दिल्ली आकर उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से इन समस्याओं पर बातचीत की. लगता है इस पहलकदमी से इन समस्याओं के समाधान की दिशा में शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे.

# इंलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी के निष्कर्ष

15 से 24 जनवरी तक जेनेवा में हुए दसवें अधिवेशन के बाद इंलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए है. इनकी क्रम संख्या है—104 व 105 पहले फैसले में कमेटी ने वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति के साथ कदम मिलाने के

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

# हरियाणा कनकास्ट को बेचने की साजिश

हरियाणा पोलीस्टील वर्कर्ज़ यूनियन की कार्यकारी समिति की बैठक 3 जुलाई को हिसार में हुई. बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष महावीर प्रसाद ने की. बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हरियाणा पोलीस्टील लिमिटेड को एक निजी क्षेत्र के उद्योगपति घराने को लीज पर दिये जाने के निर्णय तथा इसके घातक परिणामों पर विचार हुआ.

सदस्यों ने राज्य के मुख्य मंत्री भजन लाल के प्रेस बयान में इस वक्तव्य पर असहमति व रोष प्रकट किया जिसमें कहा गया था कि इस औद्योगिक संस्थान को प्रति माह 5 लाख रुपये की हानि होती थी व इसके लिए मजदूर जिम्मेदार हैं. यूनियन ने मुख्य मंत्री को याद दिलाया कि समय-समय पर यूनियन ने इस कारखाने के पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर बी. कजरींवाल की भ्रष्टता, घूसखोरी व अव्यवस्था के बारे में सरकार को सूचित किया था. इस भ्रष्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ने 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपया गैरकानूनी क्रय व विक्रय से कमाया. बी. कजरीवाल के इन गलत कामों से यह संस्थान धीरे धीरे नुक्सान में आ गया. यूनियन ने इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया कि अब जबकि सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, बी कजरी वाल के खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही हैं.

यूनियन मुख्य मंत्री के इस कथन का भी खंडन करती हैं कि यह कारखाना हर महीने 5 लाख रुपये का घाटा देता था. यूनियन ने बताया कि मार्च 1980 से कारखाने की हालत लगातार सुधर रही है. वास्तव में मई व जून के महीनों में कारखाने को कोई घाटा नहीं हुआ है.

इस संदर्भ में यह बड़ी हैरानी की बात है कि मजदूरों की इस मांग पर बिल्कुल कोई ध्यान नही दिया जा रहा है कि यह कारखाना उन्हें सौंप दिया जाए और वे इसे ईमानदारी व व्यवस्था से चलाते हुए प्रति माह कम से कम 5 लाख रुपया लाभ देंगे. मजदूरों को पूरा विश्वास है कि वे इस संथान को भली-प्रकार चला सकने में समर्थ हैं. मजदूरों ने राज्य व केंद्र सरकारों से अपील की है कि वे इस सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान को एक निजी क्षेत्र के उद्योगपति को न बेचें क्योंकि यह सरकार की घोषित राष्ट्रीय नीतियों के खिलाफ है. इसके अतिरिक्त इस संस्थान के साथ 1 हजार मजदूरों का भविष्य जुड़ा हैं.

यूनियन ने चेतावनी दी है कि निजी क्षेत्र को दिए जाने के सरकार के निर्णय के जो भी परिणाम होंगे उनके लिए सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार होगी. मजदूर अपनी नौकरियों व मजदूरी को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे.

# केंद्रीय सरकार कर्मचारी संघर्ष की राह पर

13 जुलाई को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में नेशनल काउंसिल आफ कनफेडरेशन आफ सैंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज एंड वर्कज ने 1980-81 के लिए एस मधुसूदन को अध्यक्ष व एस. के. व्यास को महासचिव निर्वाचित किया. नेशनल काउंसिल ने इस अवसर पर एक मांगपत्र भी स्वीकार किया. जिसकी मुख्य मांगे हैं— सबको बोनस मिले, वेतनमानों व महंगाई भत्ते के फार्मूले का संशोधन हो, अस्थायी मजदूरों को स्थायी बनाया जाए. सभी प्रकार के विक्टिमाइजेशन का अंत हो तथा सरकारी कर्मचारियों को पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार मिलें.

14 जुलाई को दिए गए एक वक्तव्य में बताया गया है कि कनफेडरेशन ने सरकार से कहा है कि वह अक्तूबर अंत तक बोनस के सवाल का समाधान कर दें. यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के पास इसके विरोध में कार्रवाई करने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा.

नेशनल काउंसिल ने देश भर के केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे 18 से 23 अगस्त तक की अवधि को एक मांग सप्ताह के रूप में मनाएं. इस सप्ताह बैठकों, प्रदर्शनों व धरनों के कार्यक्रम आयोजित होंगे व अगस्त में वेतन दिवस के दिन वेतन लेने से इंकार कर दिया जाए.

# बीमा कर्मचारियों द्वारा वेतन जाम नीति की निंदा

विशाखापट्टनम डिविजन के इंशोरेंस कार्पोरेशन एंप्लाईज यूनियन की छटी वार्षिक जनरल काउंसिल की मीटिंग विजाग में 21 और 22 जून को विशाखापट्टनम में हुई. दक्षिण जोन बीमा कर्मचारी फेडरेशन के संयुक्त सचिव ने अपने उद्घाटन-भाषण में सरकार के बोनस व महगाई भत्ता से संबंधित अस्पष्ट कदमों से वेतन जाम थोपने के प्रयत्नों की निंदा की. उन्होने मजदूर वर्ग को अपने वेतनों पर लगातार होने वाले हमलों को रोकने के लिए एकजुट होने को कहा.

एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई है. बीमा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है. बीमा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं जैसे जी. आइ. सी. और एल. आई. सी. के मांगपत्रों पर समझौता, आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन और इससे संबंधित समस्याओं को मान्यता देना. मकान, बोनस का अधिकार, कीमत-वृद्धि, बेरोजगारी, और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के हालात पर कई प्रस्ताव अपनाए गये.

नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर्वसम्मति से एन. कृष्णामूर्ति को अध्यक्ष व सी. जी. शंकर को महासचिव चुना.


## सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

उत्तर प्रदेश

## कपास मजदूरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी

कानपुर के कपास उद्योग के 35 हजार से अधिक मजदूर अपनी जायज मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे है. इससे पहले मजदूर अपने 11-सूत्री मांगपत्र के समर्थन में 19 मई को सांकेतिक हड़ताल पर गए थे. मजदूरों की मुख्य मांगे हैं—बिजली बंद होने की अवधि में स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के मजदूरों को पूरी मजदूरी देना, ठेका पद्धति की समाप्ति, अस्थायी मजदूरों के लिए 240 दिन काम देना, अस्थायी मजदूरों को वरिष्ठता के आधार पर स्थायी बनाना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में होने वाली धोखाधड़ी का अंत करना, काम पर मृत्यु हो जाने वाले मजदूर के परिवार को 6 साल की पूरी तनख्वाह या मुआवजे के रूप में 36,000 रुपये देना, जे. के. मैनुफैक्चरर्ज (कैलाश मिल) को जो कई वर्ष से बंद है, जल्दी खोलना व इसके कर्मचारियों को इस दौरान का वेतन देना.

सांकेतिक हड़ताल का निर्णय 13 अप्रैल को एक संयुक्त सम्मेलन में सीटू, एच. एम. एस. 'एटक', इंटक तथा अन्य यूनियनों ने लिया. बी. एम. एस. व यूटक यूनियनों ने हड़ताल का विरोध किया. सीटू यूनियनों ने हड़ताल में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया.

## रसायन मजदूर भुखमरी के कगार पर

पिछली 16 फरवरी से कानपुर स्थित कानपुर केमिकल वर्क्स लिमिटेड में तालाबंदी होने के कारण इस संस्थान के 1,500 मजदूर व उनके परिवारों के 6,500 से अधिक सदस्य भुखमरी के कगार पर हैं. संस्थान के प्रबंधकों ने श्रम विभाग व जिला प्रशासन से सांठगांठ कर रखी है और वे मजदूरों के संघर्ष को कमजोर करके उन्हें नाजायज शर्तों पर काम करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

अत्यधिक मुनाफा देने वाली इस कंपनी के मजदूर जीवनयापन व काम करने की बेहतर सुविधाओं को पाने के लिए संघर्षरत हैं. इस संघर्ष का नेतृत्व कानपुर केमिकल कर्मचारी यूनियन (सीटू) कर रही है. प्रबंधकों ने संघर्ष को दबाने के लिए यूनियन के सचिव तथा 7 अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया और गिरफ्तार करवा दिया. इस कार्रवाई के विरोध में मजदूर 7 फरवरी से हड़ताल पर गए. 16 फरवरी को प्रबंधकों ने तालाबंदी की घोषणा कर दी.

सीटू की उत्तर प्रदेश कमेटी के महासचिव दौलत राम इस सिलसिले में केंद्रीय श्रम मंत्री से मिले और उन्हें स्मरणपत्र दिया. स्मरणपत्र में मांग की गई है कि तालाबंदी को तत्काल वापिस ले लिया जाए व बातचीत के जरिये मजदूरों की मांगों पर जायज निर्णय लिया जाए. यदि प्रबंधक ऐसा नहीं करते तो सरकार को मिल अपने हाथ में ले लेनी चाहिए. इस बीच मजदूर अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं.

## रेल समाचार

[पृष्ठ बारह से आगे]

लिए प्रशिक्षण व पुनर्प्रशिक्षण पर जोर देते हुए यह कहा है कि "जो मजदूर ये प्रशिक्षण प्राप्त करके नए-नए पदों व जिम्मेदारियों को संभालते हैं उन्हें उसके अनुरूप ही अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए".

अपने दूसरे फैसले में कमेटी ने 1962 में आई० एल० ओ० के सुझाव नं० 166 की ओर ध्यान दिलाया है जिसके अनुसार काम के घंटों को धीरे-धीरे कम करके 40 घंटे प्रति सप्ताह करने की सिफारिश की गई है. इसके आधार पर कमेटी ने कहा है कि आई० एल० ओ० का यह सुझाव रेल यातायात पर भी लागू होता है. उसने अपने सदस्य राज्यों को ऐसा करने की हिदायत भी दी है. यदि कमेटी के इन दो फैसलों को क्रियान्वित किया गया तो इससे न केवल कर्मचारियों की दशा में सुधार होगा बल्कि बेरोजगार नवयुवकों के लिए नौकरी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी.

### रेलवे में कंप्यूटर

आल इंडिया रेलवेमैंज फेडरेशन के महासचिव के सर्कूलर नं० ए० आई० आर० एफ०/379 दिनांक 22/25 अप्रैल 1980 से यह स्पष्ट होता है कि दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ने 22 नवंबर 1978 को ही रेलवे बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकृति दे दी थी जिसके अनुसार वर्तमान आई० बी० एम० 1401 कम्प्यूटरों को बदलकर 3-4 जेनेरेशन के कम्प्यूटर लगाए जाएं जो पहले कम्प्यूटरों के मुकाबले 1600 गुना अधिक शक्तिशाली हैं. यह आश्चर्य की बात है कि पहले 18 महीनों में इस सुझाव व दोनों फेडरेशनों द्वारा इसे चुपचाप माने जाने के बारे में चुप्पी साधी गई व रेलवे मजदूरों को इसके परिणामों के बारे में अंधकार में रखा गया.

कम्प्यूटरों के इस परिवर्तन का असर रेलवे के सभी विभागों—क्लर्कों, कमर्शियल क्लर्कों, ट्रेन क्लर्कों तथा गार्ड, केबिन व शंटिंग स्टाफ के सभी वर्गों—पर पड़ेगा.

हालांकि रेलवे बोर्ड ने इसके असर को कम करने के लिए कुछ उपाय करने के सुझाव दिए हैं, किंतु यह स्पष्ट है कि इससे रेलवे में रोजगार की संभावनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. सीटू इस समस्या पर शीघ्र ही एक पुस्तिका प्रकाशित करेगी.

### तेल और कोयला

[पृष्ठ छः से आगे]

दिन) और यह 1976 में 870 लाख टन (1.74 बैरल प्रतिदिन) और 1970 में लाख टन था.

यहां यह ध्यान में रखना चाहिए की भारत का कोयला संचय 3,33,450 लाख टन है जबकि उसकी सालाना खपत लगभग 1,000 लाख टन ही है. इसका मतलब है कि भारत का कोयला संचय 300 से भी ज्यादा सालों तक के लिए पूरा है. ऊर्जा संकट के इस समय में कोयला शक्ति को ज्यादा उपयोग में लाने पर जोर देना चाहिए.

# ई. एस. आइ. के डाक्टरों का प्रतिव्यक्ति शुल्क बढ़ा

बहुत से प्रतिनिधि मंडलों व प्रदर्शनों की लगातार असफलता के बाद महाराष्ट्र के ई एस आइ के डाक्टरों ने इंश्योरेन्स मैडिकल प्रैक्टिशनर्ज एसोसिएशन के नेतृत्व में 1 मई से अधिक प्रतिव्यक्ति शुल्क की मांग के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी. यह हड़ताल पूर्णत: सफल रही.

कीमतों में बढ़ोतरी की बजाय इन डाक्टरों को प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति शुल्क के तौर पर प्रति बीमाकृत परिवार के लिए सिर्फ 30 रुपये मिलते थे जो कि बढ़ रही कीमतों को मद्देनजर रखते हुए नेकाफी हैं. अपना खर्चा भलीभांति चला पाने के लिए इन डाक्टरों ने प्रत्येक परिवार के लिए 60 रुपया प्रतिवर्ष की मांग की.

सीटू ने हड़ताली डाक्टरों की इस मांग का पूरा समर्थन किया. अहिल्या रंगनेकर और डा ए बी साबंत ने डाक्टरों में एक भाषण देते हुए उनके संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की.

बम्बई में इंटक के नेतृत्व ने डाक्टरों की इस मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जब तक ई एस आइ सेवाओं को संशोधित नहीं किया जाता डाक्टरों को किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं दी जानी चाहिए. इस पर हड़ताली डाक्टरों ने 15 मई को राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के कार्यालय के सामने एक विरोधी प्रदर्शन आयोजित किया.

सीटू की अगुवाई पर केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री अंजैयाह ने इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से 12 जून को अपने कार्यालय में मिलना स्वीकार किया तथा डाक्टरों की समस्याओं पर चर्चा भी की. चर्चा के दौरान इंडियन मैडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा० आर० के० मेंडा ने डाक्टरों का केस बहुत ही जोरदार शब्दों में सामने रखा. श्रम मंत्री ने मांग के औचित्य को सिद्धान्त: मंजूर किया. उन्होंने डाक्टरों से अपनी हड़ताल समाप्त कर हालात सामान्य करने की अपील की. ई. एस. आइ. डाक्टरों की एक बैठक में डाक्टरों ने अपनी मांग को सिद्धांत रूप में मान लिए जाने के कारण हड़ताल समाप्त कर देने का निश्चय किया. डाक्टरों के निवेदन पर सरकार ने ई. एस. आइ. कार्पोरेशन की बैठक की तारीख बढ़ा देना मंजूर कर लिया.

10 जुलाई को इंश्योरेन्स मैडिकल प्रैक्टिशनर्ज एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय श्रम मंत्री से मिला तथा उनसे इस मांग को सहानुभूति पूर्ण नजरिए से जांचने की अपील की.

12 जुलाई की ई. एस. आइ. कार्पोरेशन की स्थायी कमेटी में डाक्टरों की मांग पर विचार किया गया. इसमें प्रतिव्यक्ति शुल्क को 40 रुपये करते हुए प्रति परिवार के प्रति वर्ष के शुल्क में 10 रुपये बढ़ा दिए गए. डाक्टर इस निर्णय से खुश नहीं थे तथा उन्होंने प्रतिव्यक्ति शुल्क को और अधिक बढ़ाने की मांग करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखने का फैसला किया.

ई. एस. आइ. कार्पोरेजन में एटक के प्रतिनिधि ने ई. एस. आइ डाक्टरों की इस न्याय संगत मांग की सहानुभूति पूर्ण रवैये से नहीं देखा. यदि ई. एस आइ. के मजदूर प्रतिनिधियों ने डाक्टरों की मांगों का जोरदार समर्थन किया होता तो शायद उनकी प्रतिव्यक्ति फीस में अधिक बढोतरी हो जाती.

मजदूर ई. एस. आइ. योजना के काम से बहुत अप्रसन्न हैं. डाक्टरों और ट्रेड यूनियनों का सही मिलाजुला प्रयत्न ही ई. एस. आइ. के मौजूदा गलत तरीकों के खिलाफ संघर्ष करने में सहायक हो सकता है.

इंशोरेंस मैडिकल प्रैक्टिशनर्ज एसोसिएशन ने अगस्त के अंत में या सितम्बर के मध्य में अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए ई. एस. आइ डाक्टरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया है.

# एच.एस.सी.एल. प्रबंधकों द्वारा सीटू कार्यकर्ताओं पर दमन

हैदराबाद स्थित हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में 25 जून को 5 सीटू कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया. इन कार्यकर्ताओं के नाम हैं— जी. मल्लेश्वर राव, बी. रवि कुमार, एल. सत्यनारायण, सी. गांधैया व पी. सी. जान.

प्रबंधकों की इस दमनकारी नीति का उद्देश्य सीटू यूनियन को दबाना है. कई केंद्रों पर एच. एस. सी. एल. यूनियनों ने प्रबंधकों की इस कार्रवाई का विरोध किया है और मांग की है कि इन पांच कर्मचारियों को तत्काल बहाल कर दिया जाए.

# कामगार महिलाओं के लिए रेल सुविधा

मद्रास की दि वर्किंग बुमेंस कोओर्डिनेशन कमेटी ने महिला यात्रियों के लिए उपनगरीय रेल सुविधाओं की मांग करते हुए 2 जुलाई को दक्षिण रेलवे के जरनल मैनेजर के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया. इसमें डाक व तार, रेलवे राज्य, व केंद्रीय सरकार, बैंकों तथा निजी संस्थाओं में कार्यरत लगभग 100 महिलाओं ने भाग लिया. कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल रेलवे के जरनल मैनेजर से मिला तथा एक ज्ञापन दिया.

परिणाम स्वरूप दक्षिण रेलवे वालों ने मद्रास की उपनगरीय विद्युत रेलों में महिलाओं के लिए कुछ आरक्षित अतिरिक्त डिब्बों की सुविधा देना मंजूर किया. इस विजय ने महिलाओं में और अधिक उत्साह भर दिया है तथा अधिक से अधिक महिलाएं अब कोओर्डिनेशन कमेटी की ओर आकर्षित हो रही हैं.

# कामरेड दिनेन भट्टाचार्य

**14** जुलाई 1980 को सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य कामरेड दिनेन भट्टाचार्य के असामयिक निधन के दुःखद समाचार से सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज, इसकी राज्य कमेंटियां व संबद्ध यूनियनों को एक भारी धक्का पहुंचा. वे 65 वर्ष के थे.

15 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले कामरेड भट्टाचार्य हुगली जिले में ट्रेड यूनियन आंदोलन की नींव डाल उसे सक्रिय बनाने में सम्बद्ध रहे. वे दशकों तक वहां की बहुत सी यूनियनों से जुड़े रहे और साथ ही मजदूरों के हर हिस्से में बेहद लोकप्रिय थे. बिरला के हिन्द मोटर्स के मजदूरों के वे सर्वमान्य नेता थे तथा श्रीरामपुर चुनाव क्षेत्र से चार बार लोकसभा का चुनाव जीते.

कामरेड भट्टाचार्य रबड़ और टायर मजदूरों के संघर्ष से भी जुड़े हुए थे. वे आल इंडिया रबड़ एंड टायर वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे. वे रेयन मशदूरों के आंदोलन से भी सम्बद्ध रहे. वे सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष थे.

संसद सदस्य की हैसियत से ब जरूरतमंद लोगों के हितों के लिए वे सदा संघर्षरत रहे तथा सरकारी नीतियों की निर्भीक आलोचना करते रहे. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कमेटी के सदस्य रहते हुए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों में बरकरार बहुत से अपराधों को बेनकाब किया.

कामरेड दिनेन बहुत वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी के सदस्य भी रहे. संसद सदस्य बनने से पहले वे श्रीरामपुर की नगर पालिका के सदस्य भी रहे.

कामरेड दिनेन ने अंत तक एक सादा जीवन बिताया. वे अविवाहित थे.

सीटू और "सीटू मजदूर," की कामरेड दिनेन भट्टाचार्य के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ हार्दिक सहानुभूति है.

सीटू की फरीदाबाद (दिल्ली) जिला कमेटी ने कामरेड दिनेन भट्टाचार्य को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक सच्चे क्रांतिकारी थे. कामरेड दिनेन की मृत्यु का समाचार पाते ही कोयला श्रमिक संघ (सीटू) ने मध्यप्रदेश सरगुजा, चिरीमिरी क्षेत्र में कोयला मजदूरों की एक शोक सभा बुलाई. सभा में यह शपथ ली गई कि वे कामरेड दिनेन के अधूरे कामों को पूरा करेंगे तथा वामपंथी जनवादी एकता के लिए संघर्षबद्ध होंगे. मद्रास की बर्किंगम और कारनेटिक मिल्स स्टाफ यूनियन के कार्यकारी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर कामरेड दिनेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. सीटू के महासचिव को दिए गए एक संदेश में कहा गया है कि—हम मजदूर वर्ग के साथ मिलकर आपके संगठन तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को पहुंची असंशोधनीय हानि के लिए अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं. दलितों के लिए वे एक धर्मयोद्धा समान थे.

## खास नजरिया

[पृष्ठ चार से आगे]

भावना कैसे जागृत करेंगे? इसलिए, राममूर्ति ने कहा, इन सब समस्याओं के प्रति हमारा एक खास दृष्टिकोण है. हम इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन केवल तब जब आप भी उनका जबाव दें. हम मुनाफाखोर और कालाबाजारी नहीं हैं. यह तो रोजगार देने वाले हैं जो काला धन बनाते हैं. अपने भाषण का समापन करते हुए सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली आर्थिक नीतियों के इस विशाल नजरिये में इन नीतियों की रचना में आप मजदूर वर्ग को विश्वास में लेने जा रही हैं या नहीं एक बुनियादी सवाल है जो मैंने उठाया है और आशा करता हूं कि इस पर आप अपनी राय व्यक्त करेंगीं.

## एजेंट कृपया ध्यान दें

अपने एजेंटों से हम अनुरोध करते है कि वे कृपया बिल का भुगतान तुरंत कर दिया करें. ऐसा न करने से, हमें काफी परेशानी होती है. वार्षिक ग्राहक भी अपने चंदे का नवीकरण करा लें.

मैनेजर


## संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय

निरेन घोष सुघिन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)


एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित